34

संख्या: 132 / XI / 14 / 56(05)2014

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक / परियोजना समन्वयक,
केन्द्रीय परियोजना समन्वयक इकाई,
आई0एल0एस0पी0, देहरादून।

ग्राम्य विकास अनुभाग। देहरादून, दिनांक: १७ मार्च, 2014

विषय– समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (आई0एल0एस0पी0) के पुर्नसंरचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रावली सं0 01(11)1 के द्वारा दिनांक: 04.03.2014 को प्रस्तुत प्रस्ताव (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें।

प्रश्नगत प्रकरण पर वित्त विभाग द्वारा निम्न परामर्श / सहमति प्रदान की गई है–

"सहमति, जो कार्य लिए जाएं जिलाधिकारियों को पूर्ण रूप सें सूचित करें व युद्ध स्तर पर कार्य Take Up किए जाएं।"

वित्त विभाग द्वारा दिए गए उक्त परामर्श / सहमति के क्रम में समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित विकासखण्डों में प्रस्तावित प्रश्नगत क्रियाकलापों / गतिविधियों को कराए जाने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में आपदा तथा वर्तमान निर्वाचन के सम्बन्ध में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई
(CPCU)

पंजीकरण संख्या 34
दिनांक 14/3/2014
पत्रावली संख्या
शाखा H.R.M. (H.R. Section)

टीपें और आज्ञायें

संख्या

1. कृपया अवगत होना चाहें कि समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के Project Implementation Manual के अनुसार उत्तराखण्ड के 5 जनपदों यथा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, टिहरी एवं उत्तरकाशी में कार्य किया जाना था। उत्तराखण्ड राज्य में जून 2013 में पर्वतीय क्षेत्र में आयी दैवीय आपदा को देखते हुए समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के Restructuring का प्रस्ताव शासन स्तर पर अनुमोदित कर IFAD को प्रेषित किया गया। (पताका क) नोटशीट एवं प्रस्ताव की प्रति पताका क व ख में संलग्न है। दिनांक 03.03.2014 को IFAD द्वारा DEA GOI को प्रेषित स्वीकृति की प्रति पताका–'ग' पर रक्षित है।
2. उक्त के कम में दिनांक 30.01.2014 को सम्पन्न परियोजना की परियोजना प्रबन्धन कमेटी में एजेन्डा के बिन्दु संख्या 3.07 में उक्त Restructuring पर चर्चा एवं अनुमोदन प्राप्त किया गया। दिनांक 31.01.2014 को सम्पन्न परियोजना स्टीयरिंग कमेटी के एजेन्डा संख्या 3.05 में Restructuring पर चर्चा की गयी एवं इस कम में निर्देशित किया गया कि परियोजना द्वारा आपदा प्रभावित जनपदों में राज्य सरकार की विभिन्न इकाईयों द्वारा राहत कार्यो का संज्ञान लेते हुए आजीविका संवर्द्धन (Livelihoods Enhancement) कार्यो को करने हेतु उच्च प्राथमिकता पर कार्यो की Detailing की जाए व आपदा प्रभावित जनपदों में sustainable livelihoods को site specific need assessment करते हुए कार्ययोजना बनाई जाय तथा इस हेतु मुख्यालय से टीम का गठन कर आपदा परियोजना जनपदों को भ्रमण किया जाय तथा आपदा क्षेत्रों में किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाय।
3. उक्त के कम में टीम का गठन कर नये आपदा प्रभावित जनपदों यथा रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, टिहरी तथा उत्तरकाशी का भ्रमण किया गया एवं संबधित विभागों व कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/एजेन्सियों से वार्ता कर जिलेवार एवं consolidated draft रिपोर्ट तैयार की गयी है। रिपोर्ट में गतिविधिवार Detailing भी की गयी है (पताका 'घ')। परियोजना द्वारा किये गये आंकलन के आधार पर 11 पर्वतीय जनपदों के 46 विकासखण्ड आपदा से प्रभावित हुए हैं। इनजनपदों मे से जनपद जाशीमठ, कर्णप्रयाग, उखीमठ, मुन्शयारी व धारचुला आपदा से अत्याधिक प्रभावित हुए है। इन जनपदों में से जाशीमठ, कर्णप्रयाग व धारचुला को NLRM के अन्तर्गत वर्ष 2014 से सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। आंकलन के अनुसार उखीमठ विकासखण्ड में कई एजेन्सियां के द्वारा कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार मुन्शयारी जनपद में आपदा से कुल 148 परिवार प्रभावित हुए है। अतः उक्त 5 विकासखण्डों को ILSP के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

ILSP परियोजना क्षेत्र में जो विकासखण्ड अत्याधिक प्रभावित हुए है का विवरण निम्नवत है :–

SNo	Name of district	Disaster affected ILSP blocks
1	Uttarkashi	Bhatwari
2	Chamoli	Ghat
		Narayanbagar
		Tharali
4	Rudraprayag	Jakholi
		Augustmuni
5	Bageshwar	Garur
		Kapkot
	Total	8 Blocks

इसी प्रकार ILSP परियोजना क्षेत्र में जो विकासखण्ड आपदा से कम प्रभावित हुए है का विवरण निम्नवत है :–

SNo	Name of district	Less affected ILSP blocks
1	Uttarkashi	Naugaon
		Purola
		Dunda
		Mori
2	Tehri	Jaunpur
		Devprayag
		Pratapnagar
		Bhilangna
		Chamba

3	Chamoli	Dewal
		Dasholi
4	Bageshwar	Bageshwar
5	Pithoragarh	Bin
		Munakot
		Kanalichina
6	Almora	Dhauladevi
		Lamgara
		Bhainsiachana
		Hawalbagh
		Chaukhutia
		Salt
		Syaldeh
		Bhikiasen
7	Dehradun	Chakrata
		Kalsi
8	Pauri	Pabo
		Ekeshwar
		Kaljikhal
9	Nainital	Betalghat
		Ramgarh
10	Champawat	Pati
		Champawat
		Barakot
	Total	**35 Blocks**

उक्त विकासखण्डों में से जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा चिन्हित 7 विकासखण्डों के कार्यो को जलागम विकास इकाई द्वारा सम्पादित किया जायेगा। इस कम में ILSP के अन्तर्गत प्रस्तावित विकासखण्डों में की जाने वाली गतिविधियों का सारांश निम्नवत् है:-

SNo	Sector/Sub Sector	Broad Activities proposed	Specific activities identified
1	Food Security and Scaling up	Micro-irrigation infrastructure	Water tanks, micro-irrigation facilities
		Support for off-season vegetables(Quality seeds)	Pea, Potato, capsicum, cauliflower
		Support for spice crops (quality seeds)	ginger, garlic, turmeric, chilly
		Support for traditional crops(Quality seeds)	Amaranth, Mandua, Paddy, Rajma, Gahat, Urad, lentil, Soyabean, etc
		Support for Livestock development	AI, fodder bank, animal health, milk collection, shed renovation, wool shearing and marketing, goatary
		Support for medicinal plant cultivation (quality planting material)	Promotion of kuth, kutki, kalajeera, lemongrass, rosemary
		Support for Non-farm sector	Weaving centres, Blacksmithy, collective marketing, Eco tourism, paper bag production (environment friendly)
	Block expansion	Engagement of Technical agencies,	Support to technical agencies for project implementation
		Support to Producer Groups, community institutions, market support	support for community organisations
	Project operations	Establishment of monitoring offices	at district level
2	Convergence with line dept	Convergence with NRLM	coverage of one block
		Convergence for technical support in Horticulture	as per identified activities
		Convergence to be identified	identified activities as per sub-project
		Convergence with Agriculture department	Soil testing support and other support

पत्रावली संख्या

		Common facility creation in other affected blocks	convergence with identified agencies
		Support for Livestock with ULDB, USWDB, AHD etc.	Livestock Development Centres in identified clusters with ULDB
			Livestock Support centres in cluster approach with USWDB
			Livestock support centres in Yatra Routes for equines with AHD
3	Access to Market	Collection centre/Market centres	Grading and packaging facilities, weighing machines
		Market facilitation	support for market access
4	Vocational Training	Identified trades	Hospitality, Mobile repairing, Electrician, Computer Hardware, Computer based Accounting and ERP solution, Data entry operator, Sewing and Tailoring, Beautician, fruit processing, one-stop vehicle service centre, Transportation, guides for eco-tourism etc
		Training of youth	Training of youth for Police, Army, disaster preparedness. GRC/KRC linkage
5	Support for ecotourism	Support for ecotourism	Support for home stays, ecotourism
6	Project development and support for RFI	Project development and support for RFI	Rural finance and CSR linkages
7	MSME facilitation	MSME facilitation	to be worked out

उक्त गतिविधियों का कियान्वयन परियोजना इकाईयों, रेखा विभागों एवं सेवा प्रदाता एजेन्सियों के माध्यम से उत्तराखण्ड उपार्जन नियमावली, 2008 का अनुपालन करते हुये किया जाना प्रस्तावित है।

4. उक्त कम में अवगत कराना है कि ILSP हेतु पदों का सृजन का शासनादेश शासन स्तर पर विचाराधीन है एवं शासनादेश के पश्चात फील्ड स्तर पर कियान्वयन टीम की तैनाती की जायेगी एवं तदोपरान्त प्रस्तावित कार्यो की micro planning करते हुए सम्पादित किया जायेगा।
5. उक्त रिपोर्ट को सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से शासन स्तर पर अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर निर्देशों हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
6. उक्त कम में यह संज्ञान में लाना है कि लोकसभा एवं पंचायत स्तरीय चुनावों के मध्यनजर उक्त प्रस्तावित गतिविधियों को आचार सहिता से मुक्त रखने हेतु सहमति प्रदान करने का कष्ट करें।

कृपया बिन्दु संख्या 1 से 6 का अवलोकन करना चाहें तथा रिपोर्ट को सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से शासन स्तर पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

4/3/1

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, UPASaC /
मुख्य कार्यकम प्रबन्धक, UGVS

मुख्य परियोजना निदेशक / परियोजना समन्वयक,
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई, ILSP

4/03/14

पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

21

सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन

4/3/14
(विनोद फोनिया)
सचिव
पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं
उत्तराखण्ड शासन

अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड शासन

(बी०पी० पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा
उत्तराखण्ड शासन

अपर मुख्य सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन

[illegible]

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव,
वित्त, औद्योगिक विकास,
नागरिक उड्डयन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

for GO imm.

4/3
(विनोद फोनिया)
सचिव
पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं सूचना
उत्तराखण्ड शासन

US, RD

नोसं.थी.पं.
04/03/14

1. कृपया अवगत होना चाहें कि आपके अनुमोदन के पश्चात् समेकित आजीविका समेकित परियोजना की पुर्नसंरचना से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को आईफैड को प्रेषित किये गये थे। ईमेल के माध्यम से किया गया पत्राचार पताका 'क' में रक्षित है।

2. उक्त के कम में दिनांक 30 नवम्बर, 2013 को आईफैड के Country Programme Manager श्री नाईजेल ब्रैट द्वारा ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित 7 बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी है।

a- It is not clear to me how UGVS will implement an expanded work programme (incl the new funding), without expanding the UGVS staffing. You are already suffering on staffing. How do you intend to handle this?

b- I feel that any future reallocation in ILSP should be based on performance. In other words, if WMD perform better than UGVS in the first few years, I feel we should be open to a possible move of money back to WMD at MTR;

c- Please confirm to me that WMD are 100% happy with the new allocation, and that they are on-board with the new WMD allocation and reduced work areas? Are they moving yet on their work plans in their areas?

d- Please confirm to me what will happen to the watersheds that are no longer covered by ILSP? How will they be supported? Were any of these excluded watersheds affected by the floods?

e- Given the wide ranging destruction of infrastructure it is not clear how would ecotourism be promoted? Besides, it is likely that the in-flow of tourists will decline in the initial period after the floods. How will this be addressed?

f- Whereas commitment to CSR has increased and is likely to further rise following the Company's Act as mentioned but it may be useful to have an idea of what activities companies may be interested in investing? One possible way of utilizing support under CSR is to find linkage between skill development activities covered under the project with placements being provided by companies. Is that a possibility?

g- While I agree that fast tracking of implementation is needed, I remain sceptical this will happen, given the performance so far. What steps are you going to take to get things moving?

3. उक्त बिन्दुओं पर तैयार ड्राफ्ट आख्या पताका 'ख' में रक्षित है व बिन्दु संख्या 2g में वर्णित बिन्दुओं पर अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन व सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञान में लाते हुये उचित उत्तर बनाना उचित होगा। इस प्रकार अनुमोदन उपरान्त Draft reply को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् ही तदनुसार आख्या आईफैड को प्रेषित किया जाना उचित होगा।

कृपया बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 का अवलोकन करना चाहें तथा सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, UPASaC / 16/12/13
मुख्य कार्यकम प्रबन्धक, UGVS

मुख्य परियोजना निदेशक / परियोजना समन्वयक,
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई, ILSP

कृपया वार्ता हेतु, यथा निर्देश करना चाहें। 17/12/13

Vijay Kumar, IFS
Project Coordinator
CPCU, ILSP

सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन

(विनोद फोनिया)

अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन

18/12/13
(वी०पी० पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव/
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त
उत्तराखण्ड शासन

(30)

1. कृपया अवगत होना चाहें कि गत टीपें एवं आज्ञायें पृष्ठ संख्या 3 पर समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की पुर्नसंरचना के प्रस्ताव को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 में प्रदत्त अनुमोदन के उपरान्त समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की पुर्नसंरचना के प्रस्ताव का अनुमोदन माननीय कैबिनेट से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को पत्र प्रेषित किया जाना है। पत्र का आलेख पताका क में रक्षित है।

कृपया बिन्दु संख्या 1 व 2 का अवलोकन करना चाहें तथा सहमति की दशा में पताका क में रक्षित पत्रालेख पर हस्ताक्षर करना चाहें।

12/12/13

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, UPASaC /
मुख्य कार्यक्रम प्रबन्धक, UGVS

मुख्य परियोजना निदेशक / परियोजना समन्वयक,
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई, ILSP

12/12/13

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की पुर्नसंरचना हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन

1. कृपया अवगत होना चाहें कि उत्तराखण्ड में माह जून, 2013 में आयी प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखते हुऐ एवं राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की पुर्नसंरचना (Restructuring) हेतु शासन स्तर पर भारत सरकार एवं अर्न्तराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) से वार्ता की गयी।

इस कम में अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा Joint Secretary MI, Ministry of Finance भारत सरकार को प्रेषित पत्रांक 227/A.C.S./P.S./Finance/2013 दिनांक 14 अगस्त, 2013 के कम में Joint Secretary MI, Minsitry of Finance भारत सरकार के पत्रांक 10/9/2010-FB.VII 19 सितम्बर, 2013 के माध्यम से आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त किये गये। इस कम में यह अवगत कराया गया कि IFAD से समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की पुर्नसंरचना हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त की जा चुकी हैं। IFAD द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि –

IFAD is seeking a concrete proposal from the state Government of Uttarakhand on exactly what the funds would be used for to ensure that the proposed activities are in line with the existing text to the loan agreement for ILSP.

इस कम में IFAD में की गयी अपेक्षा के कम में समेकित आजीविका सहयोग परियोजना हेतु किये गये अनुबन्ध का परीक्षण किया गया एवं प्रस्तावित गतिविधियों को इसी अनुरूप चिन्हित किया गया हैं। IFAD के साथ हुये परियोजना अनुबन्ध की प्रति संलग्न की जा रही है। उक्त रूप से प्रस्तावित पुर्नसंरचना हेतु 28 मिलियन डॉलर को जलागम कार्यो से हस्तान्तरित कर आजीविका संवर्धन कार्यो में लगाया जाना प्रस्तावित है।

2. उक्त कम में मुख्य परियोजना निदेशक/परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई, ILSP द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय को प्रेषित पत्रांक 11/2013–14 दिनांक–08.10.2013 के माध्यम से पुर्नसंरचना हेतु सुझाव एवं प्रस्ताव मांगे गये थे। (पताका क)

3. उक्त के कम में जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा पत्रांक 886/11–7 (IFAD) दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 के माध्यम से 02 प्रस्ताव प्राप्त हुये है, जिसका सारांश निम्नवत् है। (पताका ख)

प्रस्ताव–1: इस प्रस्ताव में मूल 6 जनपदों में से 4 जनपदों यथा– पौड़ी गढ़वाल, चम्पावत, नैनीताल एवं पिथौरागढ़ के 20 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों जिनका कुल क्षेत्रफल 67,537 हैं0 है, व लगभग 19800 परिवार सम्मिलित हैं।

प्रस्ताव–2: इस प्रस्ताव में मूल 6 जनपदों में से केवल 3 जनपदों यथा– पौड़ी गढ़वाल, चम्पावत एवं नैनीताल के 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों जिनका कुल क्षेत्रफल 70,194 है0 है, व लगभग 19994 परिवार सम्मिलित होंगे।

(8)

जलागम प्रबन्ध निदेशालय को पौड़ी, चम्पावत व नैनीताल जनपद में कार्य किया जाना उचित होगा व समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति द्वारा जनपद टिहरी, रूद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़ के चिह्नित विकासखण्ड में कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

Project Components	Implementing agency	Before restructuring		After restructuring	
		Amt. Rs cr	%	Amt. Rs cr	%
A. Food Security & Livelihood Enhancement	UGVS	217.74 64175 HH	26.28	378.74 89795 HH	45.71
B. Participatory Watershed Development	PSWMD	471.03 39600 HH	56.85	310.03 19801 HH	37.42
C. Livelihood Finance	UPASaC	119.73	14.45	119.73	14.45
D. Project Management	CPCU	20.07	2.42	20.07	2.42
Total Project Costs (A + B + C + D)		**828.57**		**828.57**	

उक्त क्रम में IFAD द्वारा दी जाने वाली धनराशि का वित्तिय स्वरूप निम्नवत् होगा–

Rs. in crore

Project Components	Implementing agency	Before restructuring	After restructuring
A. Food Security & Livelihood Enhancement	UGVS	172.98	282.30
B. Participatory Watershed Development	PSWMD	259.21	149.89
C. Livelihood Finance	UPASaC	6.83	6.83
D. Project Management	CPCU	14.30	14.30
Total Project Costs (A+B+C+D)		**453.33**	**453.33**

5. उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के अन्तर्गत लिये जाने वाले प्रस्तावित जनपद (पिथौरागढ़ एवं रूद्रप्रयाग) प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इस क्रम में समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के पुर्नसंरचना का प्रस्ताव विकसित किया गया है जिसके अंर्तगत 28 मिलीयन डालर के समतुल्य धनराशी को जलागम संबंधित गतिविधियों से हस्तातरित कर आजीविका संबंधित गतिविधियों में प्रस्तावित किया गया है, जिसका सारांश निम्नवत् है।

SNo	Proposed activities	Cost Rs cr.	Cost USD Mn.
A	***Common facilities** for Livelihoods*		
1	Project Development: CSR linkage	10	1.74
2	MSME facilitation Unit	10	1.74
3	Product Development & Market support Unit	20	3.48
4	Ecotourism interventions	20	3.48
5	Action Research with State level Stakeholders	16	2.78
6	Skill development initiatives	11	1.91
B	***Convergence** with Line departments*	10	1.74
C	***New Blocks** & expansion of existing clusters*	64	11.13
	Total Project Costs	161	28

उपत प्रस्ताव को पताका–ग में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की प्रस्तावित पुर्नसंरचना हेतु विकसित प्रस्ताव पताका–ग की सैद्धान्तिक सहमति मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के स्तर से ली जानी प्रस्तावित है। सहमति उपरान्त सक्षम स्तर (माननीय कैबिनेट) से नियमानुसार अनुमोदन हेतु प्रस्ताव ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त प्रस्ताव को शासन की सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त IFAD को प्रेषित किया जाना है।

कृपया बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 4, एवं 5 का अवलोकन करना चाहें तथा सहमति की दशा में हस्ताक्षर कर उच्च अनुमोदन हेतु अग्रसारित करना चाहें।

21/10/13

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, UPASaC / मुख्य कार्यक्रम प्रबन्धक, UGVS

मुख्य परियोजना निदेशक / परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई, ILSP

21/10/13

सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, परियोजना प्रबन्धन समिति, ILSP

(विनोद फोनिया)
सचिव
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन

अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन व अध्यक्ष, प्रबन्धकारिणी, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति

(बी०पी० पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव/
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त
उत्तराखण्ड शासन

अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव,
वित्त, औद्योगिक विकास,
नागरिक उड्डयन, तकनीकी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन व अध्यक्ष, परियोजना स्टीयरिंग कमेटी, ILSP

A.C.S
26/11/13

29/11/2013

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन